mainly by ground fires. As per reports available from the State Governments forest areas of 931 Sq. Kms. in U.P. and 305 Sq. Kms. in H.P. were fire affected during 1995. There is no report of damage to wild life. During 1993 and 1994 the area affected by forest fires was 18 Sq. Kms, and 60 Sq. Kms. in U.P. and 17.32 Sq. Kms. and 5.69 Sq. Kms. in H.P. respectively.

(c) and (d) The Government has appointed a two member committee on 11.7.1995 to enquire into the causes of the forest fires, the extent of damage to the forest wealth and formulate a strategy to prevent the occurrence of such forest fires in future in these areas. The team has been asked to submit its report within a month.

देश में सबसे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी

1087. **श्री राघवजी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कौन-सी यात्री रेलगाड़ी सबसे ज्यादा तेज रफ्तार वाली है और इस रेलगाड़ी की प्रति घंटा रफ्तार कितनी है; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय कुछ मार्गों पर दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा अथवा उससे तेज रफ्तार की रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, उसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) 2001/2002 भोपाल नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जिसकी नई दिल्ली और आगरा कैन्ट के बीच अधिकतम अनुमेय गति 140 कि०मी० प्रति घंटा है।

(ख) जी नहीं, वर्ग "क" मार्गों पर मुहैया की गई मौजूदा अवसंरचना 160 कि०मी० प्रति घंटा तक की गति के लिए सक्षम है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

1088. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिलावार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में शामिल इन सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) सूचना विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 1995-96 के दौरान 17,3800 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति—1994 में मध्य प्रदेश सहित समूचे देश में वर्ष 1997 तक मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करवाने की परिकल्पना है।

विवरण

30 जून, 1995 को मध्य प्रदेश में जिले-वार व्यक्तियों की संख्या — टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा-सूची में

जिला	दिनांक 30.6.95 को प्रतीक्षासूची
बालाघाट	96
बस्तर (जगदलपुर)	630
बेतूल	239
भिण्ड	260
भोपाल	6705
बिलासपुर	2224
छतरपुर	110
छिंदवाड़ा	223
दमोह	105
दतिया	310
देवास	638
धार	436
दुर्ग	5225
गुणा	880
ग्वालियर	3205
होशंगाबाद	581
इन्दौर	4008
जबलपुर	3237
झबुआ	56
खण्डवा	75
खरगौन	200

मण्डला	89
मंदसौर	1035
मुरैना	583
नरसिंहपुर	226
पन्ना	95
रायगढ़	145
रायपुर	3614
रायसेन	55
राजगढ़	110
राज नंदगाव	320
रतलाम	438
रीवा	1875
सागर	1185
सरगुजा	710
सतना	1710
सिहोर	120
सिवनी	215
शहडोल	430
शहजापुर	206
शिवपुरी	1110
सीधी	285
टीकमगढ़	602
उज्जैन	708
विदिशा	220
	45537

गुजरात में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास

1089. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में डाक व तार विभाग के सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध नहीं कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में डाक व तार विभाग और दूर-संचार विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) अब तक जिले-वार और श्रेणी-वार कितने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) **डाक विभाग:** जी हां। **दूरसंचार विभाग:** जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सौराष्ट्र रीजन में डाक विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 5020 है।

(ग) सौराष्ट्र रीजन में कर्मचारियों को प्रदान किए गए क्वार्टरों की संख्या का जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

सौराष्ट्र रीजन में कर्मचारियों को प्रदान किए गए क्वार्टरों की जिला-वार और श्रेणी-वार संख्या

जिला	क्वार्टर की श्रेणी			
	I	II	III	IV
अमरेली	2	2	—	—
भावनगर	9	12	2	—
जामनगर	10	9	—	—
जूनागढ़	25	30	3	—
कच्छ	23	24	4	—
राजकोट	27	51	15	6
सुरेन्द्रनगर	5	8	—	—
कुल:	101	136	24	6

क्वार्टरों की कुल संख्या = 267

Modernisation of ship repair facilities at Rajabagan Dockyard

1090. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI MD. SALIM:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government had sanctioned modernisation of ship repair facilities at Rajabagan Dockyard in December, 1992;

(b) whether the same project was re-appraised by a Dutch Re-appraisal Mission;

(c) whether any zero date has been fixed for commencement of modernisation programme; and